

उपराष्ट्रपति से मिले असम के मुख्यमंत्री, विभिन्न विकास योजनाओं पर की चर्चा



नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से सोमवार को यहां उपराष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री की यह पहली मुलाकात है। इस दौरान असम के विकास और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मुलाकात करके उन्हें असम के विकास की कहानी के बारे में जानकारी देते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में विनम्रता, कड़ी मेहनत और समर्पण के प्रतीक राधाकृष्णन से मिलना हमेशा एक सीखने वाला अनुभव होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित असम की हमारी यात्रा में उनके निरंतर मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करेंगे।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया

वर्ष: 15 अंक: 153 पृष्ठ: 08

RNI : HPHIN/2012/48072



actionindiauna@gmail.com

हिमाचल संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड - चंडीगढ़



RKB GROUP
Rakesh Bhardwaj Group

जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में 56,880 अभ्यर्थी सफल, कट-ऑफ में 18 अंक की बढ़ोतरी, टॉप थी पर दिल्ली जोन के शुभम, कबीर

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की ने आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस्ड-2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस वर्ष परीक्षा में दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर रहे, जिन्होंने 329 अंक प्राप्त किए, जबकि जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह शीर्ष तीनों स्थानों पर दिल्ली जोन के

अभ्यर्थियों का कब्जा रहा। आईआईटी रुड़की ने परिणाम निर्धारित समय से पहले जारी करते हुए अंतिम उत्तर कुंजी भी प्रकाशित कर दी। अभ्यर्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर, जन्मतिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर की सहायता से देख सकते हैं। इस वर्ष जेईई एडवांस्ड के लिए 1,87,389 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 1,79,694 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 56,880 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। सफल अभ्यर्थी अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्रक्रिया (जेसा) की काउंसिलिंग में भाग ले

जेईई एडवांस्ड-2026 टॉपर

शुभम कुमार 330/360 अंक हासिल (दिल्ली जोन)

कुल सफल अभ्यर्थी: 56,880
सामान्य वर्ग कट-ऑफ: 92 अंक (18 अंक की बढ़ोतरी)
अब शुरू होगी JoSAA काउंसिलिंग



ऑल इंडिया रैंक: 1

जश्न मनाया

कट-ऑफ में 18 अंक की बढ़ोतरी, टॉप थी पर दिल्ली जोन के शुभम, कबीर और जतिन

सकेगे। सफल अभ्यर्थियों में 10,107 छात्राएं भी शामिल हैं। इस बार सामान्य वर्ग की कट-ऑफ 92 अंक रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 अंक अधिक है। विषयवार

कट-ऑफ 8 अंक निर्धारित की गई। लगभग 31.65 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। जोन के आधार पर भी कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया। आईआईटी मद्रास जोन से मोहित शेखर शुक्ला चौथे स्थान पर रहे। आईआईटी मुंबई जोन के बी. जयकृष्ण श्रीनिवास ने छठा स्थान हासिल किया।

फास्ट न्यूज

भारत में जी नेटवर्क दिखाएगा फीफा विश्व कप के मुकाबले

नई दिल्ली। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। फीफा विश्व कप 2026 का प्रसारण भारत में जी नेटवर्क करेगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने टूरनामेंट के प्रसारण और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल करने की घोषणा की है। समझौते के तहत विश्व कप के मुकाबलों का सीधा प्रसारण जी समूह के हाल ही में शुरू किए गए चार नए खेल चैनलों पर किया जाएगा, जबकि जी5 पर सभी मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। यह घोषणा टूरनामेंट के शुरू होने से करीब दो सप्ताह पहले की गई है। 11 जून से 19 जुलाई तक आयोजित होने वाला यह विश्व कप अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। जी समूह इससे पहले आई-लीग और उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग जैसे खेल आयोजनों का प्रसारण कर चुका है। इसी महीने कंपनी ने अपने यूनाइटेड 8 समूह के तहत चार नए खेल चैनल भी लॉन्च किए थे और इसके बाद फीफा के साथ अधिकारों को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। जी एंटरटेनमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गायनका ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, "हम दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं। फुटबॉल क्षेत्र और भाषा की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ता है।"

सुप्रीम कोर्ट को पांच नए जज मिले, राष्ट्रपति ने नियुक्ति पर लगाई मुहर

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उच्चतम न्यायालय के लिए पांच जजों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नाग, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे वरिष्ठ वकील वी मोहन को उच्चतम न्यायालय का जज नियुक्त किया है।

जीएसटी राजस्व संग्रह मई में 3.2 फीसदी बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये के पार

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। देश के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह 3.2 फीसदी बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। पिछले साल मई में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी महानिदेशालय ने सोमवार को आंकड़ों में बताया कि जीएसटी राजस्व संग्रह में यह वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में सुधार तथा आयात मिलने वाले कर संग्रह में लगातार बढ़ोतरी के कारण हुई है। आंकड़ों के अनुसार मई के दौरान घरेलू लेन-देन से केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) संग्रह 37,397 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 45,143 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 51,990 करोड़ रुपये रहा।

एचपी-रेडी परियोजना से आपदा तैयारी, न्यूनीकरण और पुनर्वास प्रणाली होगी मजबूत

मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रित से प्रतिरोध केंद्रित प्रशासन अपनाने पर दिया बल

टीम एक्शन इंडिया पंजाब शर्मा शिमला। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। इस क्रम में सरकार ने 2,688 करोड़ रुपये की 'हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन प्लान डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्करीड्यू (एचपी-रेडी) परियोजना शुरू की है, इसका उद्देश्य प्रदेशभर में आपदा-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। यह परियोजना जनवरी 2026 से नवंबर 2030 तक लागू की जाएगी और इसमें आपदा से निपटने की तैयारी, आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्वास तंत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण उल्थन परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में 66 से अधिक बादल फटने की घटनाएं, 234 भूस्खलन और 121 फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन आपदाओं से बड़ी संख्या में जन हानि हुई है तथा सार्वजनिक अवसंरचना और निजी संपत्ति को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त आपदा के कारण सामान्य जनजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एचपी-रेडी परियोजना के तहत आपदा प्रभावित सार्वजनिक अधोसंरचना जैसे परिवहन नेटवर्क, पेयजल योजनाएं, स्वच्छता प्रणालियां तथा विद्युत अवसंरचना इत्यादि को पुनर्स्थापित और सुदृढ़ किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य आजीविका और रोजगार के अवसरों को सृजित करना तथा आपदा जोखिम

आधारभूत परियोजनाओं लागू करने तथा व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग में बढ़ोतरी का भी फैसला किया गया

भारत-म्यांमार में आर्थिक, सुरक्षा सहयोग पर बनी सहमति

वार्ता

भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ उसकी भूमि का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा: म्यांमार

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। भारत और म्यांमार ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग तथा संपर्क सुविधाओं के विस्तार पर सहमति व्यक्त की है। आधारभूत परियोजनाओं लागू करने तथा व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग में बढ़ोतरी का भी फैसला किया गया। इसके साथ ही पड़ोसी देश की ओर से आशवासन दिया गया है कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ उसकी भूमि का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाईंग के बीच सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई। चर्चा में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों देशों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए केनविटिविटी को महत्वपूर्ण माना। इसके तहत



पारस्परिक लाभकारी आर्थिक संबंध और साझा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से क्षेत्र में पारस्परिक लाभकारी आर्थिक संबंध और साझा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि भारत, म्यांमार के एक दृढ़ और विश्वसनीय सहयोगी के रूप में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विदेश सचिव के अनुसार भारत ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना

समर्थन दोहराया है। वहीं म्यांमार के राष्ट्रपति ने आशवासन दिया कि म्यांमार की भूमि का इस्तेमाल भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा कि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, जिसके साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागर और इंडो-पैसिफिक नीतियों के केंद्र में स्थित है।

कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के कालेवा-यागी खंड के जलमार्ग पर भी बल दिया गया। वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाईंग की आधिकारिक यात्रा ने म्यांमार और भारत के बीच दीर्घकालिक मित्रता और घनिष्ठ साझेदारी की पुष्टि की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग को और मजबूत करने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया। राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाईंग ने भारत में अपने प्रवास के दौरान उन्हें और उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को दिए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आपसी सहमति से तय की गई तारीखों पर म्यांमार आने का निमंत्रण भी दिया।

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की

भारत आगमन से पहले म्यांमार के राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर, महाबोधि धर्मईखा मठ और सुजाता मंदिर का दौरा किया। यह यात्रा दोनों देशों के गहरे बौद्ध, धार्मिक और जन-जन के संबंधों को दर्शाती है। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री और म्यांमार के राष्ट्रपति ने वार्ता में पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की और संबंधों के लिए आगे की राह तय की। राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) नीतियों के संगम पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने अतिथि के सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन किया। वार्ता के बाद शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत किया।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को दिए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आपसी सहमति से तय की गई तारीखों पर म्यांमार आने का निमंत्रण भी दिया।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाईंग का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मु ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, भारत-म्यांमार के बीच की साझा बौद्ध विरासत सदियों पुराने आपसी संबंधों को एक अनोखी गर्मजोशी प्रदान करते हैं।

फिर महंगा हुआ कर्मशिवल गैस सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर के भाव में बदलाव नहीं

नई दिल्ली। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। हालांकि कीमत में की गई ये वृद्धि सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कर्मशिवल गैस सिलेंडर और पांच किलोग्राम वाले छोटू सिलेंडर तक ही सीमित है। घरेलू इस्तेमाल में आने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कर्मशिवल गैस सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये से लेकर 53.50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। सिलेंडर की नई कीमत लागू हो गई है। इससे पहले पिछले महीने के पहली तारीख यानी एक मई को कर्मशिवल सिलेंडर की कीमत में लगभग एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में ये बढ़ोतरी 993 रुपये की थी, जबकि कोलकाता में कर्मशिवल गैस सिलेंडर की कीमत 998.50 रुपये हो गई थी।

टीएमसी विधायकों पर भाजपा जॉइन करने का दबाव: ममता बनर्जी

टीम एक्शन इंडिया कोलकाता। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को फेसबुक पर वीडियो भेजे जा रही भाजपा और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस टीएमसी विधायकों पर पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का दबाव बना रही है। ममता ने दावा किया कि कुछ विधायकों और सांसदों को डरावने-धमकाने या रिश्वत देकर टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा- जो लोग टीएमसी छोड़कर गए हैं, उनके जाने से पार्टी का भला ही हुआ है। ममता का वीडियो भेजे जा रही टीएमसी के भीतर टूट की खबरों के बीच आया है। पार्टी ने आज अपने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किया है। दोनों पर पार्टी के खिलाफ बयान देने और बैठकों से दूर रहने के आरोप हैं। टीएमसी



सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह चौकाने वाला है। बेले च्यू अस्पताल के डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन उन्हें इलाज नहीं करने के निर्देश दिए गए। यह कैसा अजीब और तानाशाही रवैया है? बेले च्यू अस्पताल के लोग पहले मेरे पैर छूते थे। आपके बिड़ला और लोढ़ा परिवारों से करीबी संबंध और कारोबारी रिश्ते थे, और आप उनके सामने झुकते थे। हमारे मेजर ने सारी व्यवस्था संभाली थी। छह महीने पहले ही हमने अपोलो अस्पताल का लाइसेंस रिव्यू किया था।

मुख्यमंत्री ने बैठक में 16 में से 13 मामलों का किया समाधान

टीम एक्शन इंडिया गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी ने कहा कि अधिकारी जन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान करना है, इसलिए प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता के साथ संवाद बनाए रखें और समस्याओं के समाधान के



लिए सकारात्मक एवं जवाबदेह दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक

प्रभावी एवं जनहितकारी बन सके। मुख्यमंत्री सोमवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कठ निवारण समिति की बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में

जनसुनवाई

सीएम नायब सिंह सेनी बोले, सड़क सुधार कार्यों में समन्वय से कार्य करें सभी विभाग

कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 13 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि तीन मामलों को आगामी बैठक तक लांबित रखने के निर्देश दिए।

पेपर लीक से ध्वस्त हो रही शिक्षा व्यवस्था, युवाओं का भविष्य संकट में: पवन खेड़ा

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। कांग्रेस के केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि देश में लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और कई छात्र मानसिक दबाव में आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और कई अनियमितताओं के चलते युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

भाजपा के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक, संगठन के व्यापक विस्तार पर मंथन

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संगठनात्मक बदलावों और आगामी चुनावों की तैयारियों पर मंथन के लिए सोमवार को पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की मेरारथन बैठक चल रही है। भाजपा के विस्तार कार्यालय में करीब ढाई बजे शुरू हुई बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे हैं। बैठक में सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री संगठन बीएल रांथो, महामंत्री विनोद तावड़े, संतोष मोहन अग्रवाल, तरुण चुगु, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष



मौजूद हैं। इस बैठक के मुख्य बिंदु केंद्र में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों की रूपरेखा तैयार करना, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और विभिन्न राज्यों में पार्टी की गतिविधियों का

आकलन और आगामी चुनावों की तैयारियों एवं संगठनात्मक बदलावों पर विस्तृत मंथन करना है। बैठक से बाहर आते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने मीडिया को बताया कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक पार्टी के विस्तार कार्यालय में आयोजित की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता नितिन नवीन कर रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार 12 वर्ष पूरे होने और उल्लेखनीय कार्यों को जनता तक ले जाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।



दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों/ लीजधारकों को वितरित किए भूमिधरी अधिकार पत्र, *मौलवी-मौलाना हमें न बताएं, गाय हमारी माता है, जन्म-जन्मांतर का नाता है, गाय को पशु बोलने वाले मौलानाओं की बुद्धि पशु वाली: मुख्यमंत्री, गोमाता के साथ हिमाकत करने वाले चेलों को समझाएं, वरना ऐसी दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी: सीएम

दो टुक

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हम उन्हें बता दें कि गाय हमारी माता है, जन्म-जन्मांतर का नाता है: सीएम



'किसी मौलाना ने हिंदुओं के कल्लेआम पर मुंह नहीं खोला'



टीम एक्शन इंडिया बिजनौर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गाजियाबाद की घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए दो-टुक कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई स्वीकार्य नहीं है। जो अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है, वह गलती कर रहा है। कुछ मौलवी-मौलाना बयान दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हम उन्हें बता दें कि गाय हमारी माता है, जन्म-जन्मांतर का नाता है। माता-पुत्र के बीच कुछ भी घोषित करने की आवश्यकता नहीं। किसी पुत्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मां का सम्मान करो। हम मां और गाय दोनों के प्रति एक जैसा सम्मान का भाव रखते हैं। पशुवत तुम्हारी बुद्धि व सोच है, जो हमारी गोमाता को पशु बोलते हो। यह तुम्हारा दोषलापन है, जो गोकर्षी को प्रश्रय देते हो। सीएम

सीएम योगी ने पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी विरासत को कुंवर सुरेश सिंह संभाल रहे हैं। पाकिस्तान से विस्थापित हजारों परिवारों, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान की मजहबी कट्टरता ने 1946, 47 व 48 में जबूरन कब्जा कर निर्दोष हिंदुओं व सिखों का कल्लेआम किया था। वर्ष-दशक बीतते गए, आज चौथी पीढ़ी

पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह का स्मरण किया

ने कड़ी चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर गोमाता का चित्र लगाकर बकरीद की बधाई देने वाले अपने चेलों को समझा लो कि गोमाता के साथ हिमाकत की तो ऐसी दुर्गति होगी कि कई

पीढ़ियां याद करेंगी। यूपी में गोहत्या का मतलब तो तुम जान ही रहे हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में कई परिवारों के जीवन में खुशियों की नई रोशनी फैलाई। उन्होंने

पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए। बिजनौर ने इतिहास बनते और बिगड़ते भी देखा

महात्मा विदुर की पावन धरती बिजनौर को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महाभारत की धरती है। महाभारत से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म

उसकी रक्षा करता है। जो स्वार्थ के लिए धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसे भी नष्ट कर डालता है। यह उद्धोषणा दुनिया में अक्षरशः साबित हो रही है। यह भारत के इतिहास को बनाने वाली धरा है।

सीएम ने कहा कि वक्फ के नाम पर यहां हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा है। ये लोग इन संपत्तियों को विस्थापितों को फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि इनकी भी कुछ संवेदना है। मुंह में कुछ और पीछे कुछ, यही दोगला चरित्र होता है। सीएम योगी ने खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के कल्लेआम पर एक भी मौलवी-मौलाना ने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश में हिंदू 22 फीसदी से घटकर 7 और पाकिस्तान में 14 से घटकर महज 2 प्रतिशत रह गया। मौलाना पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। ये मौलाना जुमे की नमाज में यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और घंटिया स्तर पर काम कर रहा है। भारत के बहादुर जवान दुश्मन के ठिकाने पर जाकर उन्हें सबक सिखाने का ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन, किसी मौलवी-मौलाना ऐसा नहीं किया। सीएम ने बकरीद पर होने वाली हरकतों पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गोमात है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हैं, तब त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से हो पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, मौलाना पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। ये मौलाना जुमे की

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न

धान खरीद

खरीद विपणन वर्ष 2025-26 के धान निष्पादन और आगामी सीजन में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा



ओपी चौधरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उप मंत्रीमण्डलीय समिति के बैठक में खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के निष्पादन एवं कस्टम मिलिंग तथा आगामी खरीद सीजन में धान खरीदी के

तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, वित्त विभाग के सचिव रोहित यादव, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना, मार्केटिंग के एमडी जितेंद्र शुक्ला, मंडी बोर्ड के एमडी श्री महेन्द्र सिंह सवन्नी सहित अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पंजाब के बठिंडा, श्रीमुक्तसर साहिब शहर और अमृतसर से बठिंडा रेल मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता की जांच की। इसमें जियो और एयरटेल का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जहां बठिंडा में जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 198.27 एमबीपीएस और एयरटेल की 151.88 एमबीपीएस दर्ज की गई। केन्द्रीय संचार मंत्रालय ने बताया कि इन परीक्षणों में कॉल सेटअप सफलता दर, कॉल ड्रॉप दर, क्वेज़, डेटा डाउनलोड और अपलोड स्पीड जैसे प्रमुख मानकों को परखा गया। परीक्षण के दौरान सभी कंपनियों के सिम कार्ड से 2जी, 3जी, 4जी और 5जी नेटवर्क पर कॉल और डेटा सेशन चलाए गए और उन्नत उपकरणों से उनकी

स्पीड टेस्ट

बठिंडा में जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 198.27 एमबीपीएस और एयरटेल की 151.88 एमबीपीएस दर्ज की गई

नियंत्रण की गई। बठिंडा शहर में एयरटेल और जियो का नेटवर्क सबसे बेहतर पाया गया, जहां कॉल ड्रॉप दर लगभग शून्य रही और डेटा डाउनलोड स्पीड क्रमशः 151.88 एमबीपीएस और 198.27 एमबीपीएस दर्ज की गई। वहीं वीएसएनएल का प्रदर्शन कमजोर रहा, जहां क्वेज़ गैप और कॉल ड्रॉप की समस्या अधिक दिखी। वॉडफोन आईडिया की औसत डाउनलोड स्पीड 34.07 एमबीपीएस रही।

महिला सशक्तिकरण और मातृ-शिशु कल्याण योजनाओं से बदल रही जिंदगी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कोंडागांव जिले के ग्राम बड़ेकनेरा में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और स्व-सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, सुरक्षित मातृत्व, पोषण और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में स्थायी



सकारात्मक परिवर्तन लाना है। उन्होंने कहा कि जब किसी योजना का लाभ सीधे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है, तभी सुशासन का उद्देश्य सार्थक होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सुरक्षित मातृत्व को मिला बल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना

योजना की हितग्राही श्रीमती मनिता मरकाम और श्रीमती खेमलता कोराम को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को समय पर पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह योजना

पर्नाड रिकार्ड इंडिया ने रॉयल स्टैंग बैरल सिलेक्ट रिजर्व व्हिस्की लॉन्च की, एक नया और अनोखा वैरिएंट

टीम एक्शन इंडिया सोलान: 2026 पर्नाड रिकार्ड इंडिया के रॉयल स्टैंग बैरल सिलेक्ट ने अपने नए वैरिएंट रॉयल स्टैंग बैरल सिलेक्ट रिजर्व व्हिस्की के लॉन्च की घोषणा की है। यह नया उत्पाद उन खास ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो हर घूंट में अलग पहचान, गहराई और बेहतरीन अनुभव की तलाश करते हैं। यह नया वैरिएंट भारतीय व्हिस्की में उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति ब्रॉड की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस नए वैरिएंट में लंबी

और आकर्षक बोटल दी गई है, जो प्रीमियम लुक और एलिगेंस का एहसास कराती है। इसके साथ एक प्रीमियम क्लियर-ऑन-क्लियर लेबल दिया गया है, जो इस श्रेणी में पहली बार पेश किया गया है। इस नए उत्पाद को मास्टर ब्लेंडर केविन बाल्मफोर्थ का समर्थन प्राप्त है, जो इसकी गुणवत्ता और विशेषज्ञता को और मजबूत बनाता है। ट्रिपल सिलेक्ट प्रीमियम की गारंटी के साथ तैयार की गई रॉयल स्टैंग बैरल सिलेक्ट रिजर्व व्हिस्की में तीन बेहतरीन विशेषताओं का समावेश किया गया है।

गडकरी ने आंध्र प्रदेश की 8,512 किमी परियोजनाओं की समीक्षा की

सड़क सुरक्षा

बारिश के दौरान यातायात में व्यवधान कम हो और सड़क सुरक्षा व टिकाऊपन सुनिश्चित किया जा सके।

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश की 8,512 किमी लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की। यह समीक्षा मीडिया और सोशल मीडिया से प्राप्त



सुझावों के आधार पर की गई। मंत्रालय ने बताया कि सोमवार को यहां हुई बैठक में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, राष्ट्रीय राजमार्ग

प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और परियोजना डेकैडर शामिल हुए। गडकरी ने बैठक में समयबद्ध कार्यान्वयन,

सख्त गुणवत्ता मानकों का पालन और आधुनिक निर्माण तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे राजमार्गों की आयु बढ़ेगी, संपर्क सुगम होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित होगी। केन्द्रीय मंत्री ने अधिकारियों को व्यापक मानसून तैयारी के निर्देश भी दिए। इसमें निवारक उपाय, प्रभावी जल निकासी प्रबंधन और मजबूत प्रतिक्रिया प्रणाली शामिल हैं, ताकि बारिश के दौरान यातायात में व्यवधान कम हो और सड़क सुरक्षा व टिकाऊपन सुनिश्चित किया जा सके।

रीमा सोनी का जोरदार स्वागत किया



टीम एक्शन इंडिया सिस्सा (राजबीर खटक) उकरलाना नगरपालिका की नवनिर्वाचित चेयरपैन रीमा सोनी वरिष्ठ काँग्रेस नेता स्व. पंडित होशियारी लाल शर्मा के कार्यालय पहुंची। यहां पहुंचने पर स्व. शर्मा के पुत्र प्रदेश काँग्रेस प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा और राजेश शर्मा ने रीमा सोनी का जोरदार स्वागत किया। शर्मा परिवार ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। इस दौरान राजकुमार शर्मा ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए नगरपालिका चुनाव में रीमा सोनी की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सत्ताधारी भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने उकलाना में डेर डाल लिया था।

स्वागत

नगरपालिका चुनाव में रीमा सोनी की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है।

और जनसेवा की जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कलम के माध्यम से रीमा सोनी उकलाना में व्याप्त समस्याओं का एक-एक कर समाधान करेंगी और क्षेत्र को एक स्मार्ट व आदर्श नगर के रूप में विकसित करेंगी। रीमा सोनी के पिता जी महेंद्र सोनी पूर्व पाण्ड और माता जी श्रीमती मलहादा सोनी थे। रीमा सोनी ने शर्मा परिवार का आभार जताया और आश्वासन दिया कि वे उकलाना क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगी। इस मौके पर देवेन्द्र सोनी, प्रदीप सैनी, विशाल सोनी, शेखर सोनी, मिर्कू सरदार, राजकुमार चंद, मोहन खत्री, संदीप गर्ग, विशाल गर्ग, नीरज सोनी आदि मौजूद रहे

प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में प्रमाणीकरण छानबीन समिति की हुई बैठक

टीम एक्शन इंडिया रायपुर: आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष, नवा रायपुर में संपन्न हुई। बैठक में कुल 19 प्रकरणों की समीक्षा एवं सुनवाई की गई, जिसमें कुल 07 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये एवं 12 प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किये गए। सुनवाई हेतु रखे गए कुल 07 प्रकरणों में से 04 प्रकरणों पर सुनवाई पूर्ण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए

गए, 02 प्रकरणों पर पुनः अवसर प्रदान करने एवं 01 प्रकरण पर पुनः सोशल स्टेटस प्रस्तुत करने हेतु विजिलेंस टीम को निर्देशित किया गया। बैठक में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास डी. राहुल वेंकट (सदस्य), संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान श्रीमती हिना अनिमेष नेताम (सदस्य सचिव), संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय ऋतुराज रघुवंशी (सदस्य), संचालक, भू अभिलेख, विनात नंदनवार, संयुक्त संचालक, टीआरटीआई श्रीमती गायत्री नेताम (प्रभारी अधिकारी, जाति जांच प्रकोष्ठ),



श्रीमती रमा उड्के (सदस्य) सहित जाति जांच प्रकोष्ठ के प्मिनुअल लकड़ा (डीएसपी), जितेंद्र गुप्ता एवं श्रीमती अंजनी भगत इत्यादि उपस्थित थे। समिति के विचारार्थ रखे गए कुल 12 प्रकरणों में से 02 प्रकरणों पर

गुण-दोष के आधार पर एवं 05 प्रकरणों पर सकारात्मक विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय जनजाति आयोग से प्राप्त 01 प्रकरण (55 बैग) पर गौरला-पैण्डा-मरवाही एवं अनुविभागीय

अधिकारी (राजस्व) मस्तुरी, दोनों जिलों के सहायक आयुक्त एवं उच्चस्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के विजिलेंस सेल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकरणों की गहन जांच हेतु संबंधित जिलों में परिभ्रमण कर मिसल अभिलेख, वंशावली, एवं सोशल स्टेटस का सत्यापन/परीक्षण किये जाने के निर्देश दिए गए जबकि शेष 04 प्रकरणों पर सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण कि उक्त 12 में से दो प्रकरणों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विभाग द्वारा किया जा रहा यह प्रयास निश्चित

ही समान न्याय एवं प्रक्रियागत पारदर्शिता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा नियमित अंतराल में बैठक आयोजित कर जाति प्रमाण पत्र एवं सामाजिक स्थिति से संबंधी प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबद्ध प्रकरणों पर भी नियमानुसार पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से सुनवाई कर प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। आज की बैठक में बड़ी संख्या में पक्षकार एवं अधिवक्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए।

19 प्रकरणों पर की गई सुनवाई, 11 प्रकरणों में सुनवाई पूर्ण- आदेश जारी करने के निर्देश

राज्यपाल ने एनसीसी माउंट दियो टिब्बा अभियान-2026 को झंडी दिखाकर किया खाना

अनुशासन

» एनसीसी चरित्र निर्माण, नेतृत्व, देशभक्ति और अनुशासन का प्रतीक : राज्यपाल



टीम एक्शन इंडिया शिमला। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोक भवन, से राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के माउंट दियो टिब्बा अभियान-2026 को झंडी दिखाकर खाना किया। यह हिमालयी पर्वतारोहण अभियान पर जाने वाले कैडेट्स एवं स्टाफ के लिए आयोजित औपचारिक समारोह था।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्हें साहस, अनुशासन और टीम भावना की उत्कृष्ट परंपराओं को बनाए रखने

के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि साहसिक गतिविधियां युवाओं में आत्मविश्वास, सहनशक्ति, नेतृत्व क्षमता तथा दृढ़ संकल्प की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कविंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, देशभक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। यह युवाओं में जिम्मेदार नागरिक बनने व नेतृत्व की भावना का विकास

करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभियान और गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिभागी फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रसेवा के प्रेरक दूत बनकर उभरते हैं। उन्होंने कहा कि साहसी, अनुशासित और समर्पित युवा ही विकसित भारत की सशक्त नींव हैं।

राज्यपाल ने कहा कि माउंट दियो टिब्बा अभियान में भाग ले रहे कैडेट्स देश की युवा शक्ति की अपार क्षमता और सामर्थ्य का

प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका समर्पण, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने अभियान दल को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह चुनौतीपूर्ण अभियान उनके साहसिक जज्बा, आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा।

6,001 मीटर की ऊंचाई तक संचालित होने वाला माउंट दियो टिब्बा अभियान एनसीसी के प्रमुख पर्वतारोहण अभियानों में से एक है। इस दल में देशभर से कठोर चयन प्रक्रिया और विशेष प्रशिक्षण के बाद चुने गए कैडेट्स शामिल हैं। इन कैडेट्स को अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान (एबीवीआईएमएएस), सोलंग वैली में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

ल्यूमिनस पॉवर टेक्नोलॉजी गगरेट के लिए साक्षात्कार 4 व 5 को

राजन पुरी

ऊना। ल्यूमिनस पॉवर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-1 और 4 राम नगर, गगरेट के लिए पुरुष वर्ग में 50 पदों के लिए अप्रेंटिसेज की आवश्यकता है। साक्षात्कार 4 जून को सुबह 10.30 जिला रोजगार कार्यालय ऊना और 5 जून को उप रोजगार कार्यालय अंब में आयोजित किया जाएगा।

यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी उना अक्षय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं, आईटीआई एवं डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आयु सीमा 19 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, 12वीं पास के लिए 12,750 रुपये, आईटीआई पास के लिए 13,250 रुपये तथा डिप्लोमा धारक के लिए 14,250 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।

शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन, पंजाब से दबोचा चिट्ठा-आईस सप्लायर

नशा

» 196 ग्राम हेरोइन और 47 ग्राम आईस (मेथामफेटामाइन) बरामद



गाम आईस और 60 हजार 400 रुपये की नकदी बरामद हो चुकी है। यह जानकारी एसपी मुख्यालय अभिषेक ने मीडिया से रूबरू होते हुए दी।

एसपी शिमला (हेडक्वार्टर) अभिषेक ने बताया कि 29 मई 2026 को पुलिस थाना ढली में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में कारवाई करते हुए पुलिस ने ढली क्षेत्र से दो आरोपियों अर्वांका नेगी और प्रद्युम्न ठाकुर को गिरफ्तार किया था। दोनों के

कब्जे से करीब 65 ग्राम हेरोइन और 20 ग्राम आईस बरामद की गई थी। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ, तकनीकी विश्लेषण और बैकवर्ड लिंकेज जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनके आधार पर पंजाब के खरड़ में दबिश देकर मुख्य सप्लायर समर सिंह उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी समर सिंह के कब्जे से करीब 131 ग्राम हेरोइन, 27 ग्राम आईस और 60 हजार 400 रुपये की नकदी बरामद की है।

जिला परिषद चंबा पर कांग्रेस का कब्जा, 18 में से 10 सीटों पर शानदार जीत

हामिद खान

चंबा। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों में जिला परिषद चंबा पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 18 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 10 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ स्थापित की है।

वहीं भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को 5 सीटों पर सफलता मिली, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे।

चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विजयी



उम्मीदवारों का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने ढोल-गाइडों और मिठाइयों के साथ जीत का जश्न मनाया तथा इसे जनता के विश्वास और विकासपरक राजनीति की जीत बताया।

चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की

जीत पर जिले की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह जनता का विश्वास और विकास का प्रतीक है। जनता ने विकास, पारदर्शिता और जनसेवा की राजनीति को समर्थन देकर अपना स्पष्ट संदेश दिया है।

विधायक ने कहा कि जिला परिषद में कांग्रेस को मिला बहुमत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति देगा। उन्होंने सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देंगे।

टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ट्रायल 4 को

राजन पुरी

ऊना। अंतर जिला सीनियर टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में जिला उना टीम के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल 4 जून को सुबह 8.30 बजे इंदिरा ग्राउंड में होगा।

यह जानकारी जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मदन पुरी ने दी। उन्होंने बताया कि ट्रायल में वही खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, जिनका हिमाचली बोनाफाइड हो।

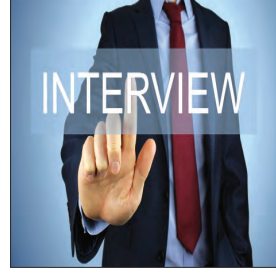
उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी अपने पहचान पत्र साथ लेकर आएँ। यह टूर्नामेंट 8 जून से पेखुबेला ग्राउंड और संतोपागढ़ ग्राउंड में खेला जाएगा।

सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्ड के 80 पदों के लिए साक्षात्कार 5 व 6 जून को

राजन पुरी

ऊना। सिस इंडिया लिमिटेड, आरटीए हमीरपुर द्वारा पुरुष वर्ग में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 80 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 5 जून को सुबह 10.30 बजे रोजगार कार्यालय उना तथा 6 जून को उप रोजगार कार्यालय अंब में आयोजित किया जा रहा है।

जिला रोजगार अधिकारी उना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण व अनुभवी, न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, आयु सीमा 19 से 40 वर्ष और वेतन 17,500 से 24 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि एक महीने की ट्रेनिंग के उपरांत



अभ्यर्थियों को नियुक्ति एटीएम, अस्पतालों, औद्योगिक क्षेत्र, मॉल सहित अन्य संस्थानों में की जाएगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ साक्षात्कार में हिस्सा ले सकते हैं।

चनावग-नेहरा क्षेत्र के बीडीसी चुनाव में मेद राम बने बीडीसी सदस्य, 649 मत लेकर दर्ज की शानदार जीत

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। चनावग-नेहरा क्षेत्र के पंचायत समिति (बीडीसी) चुनाव में ग्राम पंचायत चनावग के मेद राम ने 649 मत प्राप्त कर शानदार जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पूर्ण चंद को 94 मतों के अंतर से पराजित किया। चुनाव परिणामों के अनुसार पूर्ण चंद को 555 मत, मदन लाल को 382 मत तथा लायक राम को 390 मत प्राप्त हुए। वहीं विजेता मेद राम को कुल 649 मत मिले, जो सभी प्रत्याशियों में सर्वाधिक रहे। मतगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल 1976 वैध मत पड़े, जबकि 16 मत अवैध घोषित किए गए। इसके अलावा 10 मत 'नोटा' के



पक्ष में पड़े। इस प्रकार कुल 2002 मतदाताओं ने अपने मतार्थिकार का प्रयोग किया। मेद राम की जीत के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि नए बीडीसी सदस्य पंचायत समिति में क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे।

पंचायती चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ : अनुराग सिंह ठाकुर

टीम एक्शन इंडिया

हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पंचायतीराज एवं नगर निकाय चुनावों के परिणामों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनता का स्पष्ट जनादेश बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर से आए परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जिला परिषद चुनावों में 19 सीटों में से कांग्रेस केवल एक सीट जीत पाई, जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की और शेष सीटों पर भी कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में उनकी

पाटी का इतना कमजोर प्रदर्शन जनता की नाराजगी का स्पष्ट संकेत है।

उन्होंने कहा कि पंचायत समिति (बीडीसी) चुनावों के परिणाम भी कांग्रेस सरकार की विफलताओं की कहानी स्वयं बयान कर रहे हैं। हमीरपुर जिले की कुल 119 पंचायत समिति सीटों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 80 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 32 सीटों तक सिमट गई। सात सीटों पर निर्दलीय अथवा न्यूट्रल उम्मीदवार विजयी रहे। उन्होंने कहा कि लगभग दो-तिहाई सीटों पर भाजपा की जीत यह दर्शाती है कि जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में जनता को निराशा ही हाथ लगी है। कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम जनता से किए गए वादे अधूरे पड़े हैं। यही कारण है कि स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए भाजपा के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है।

जनता ने नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि कांग्रेस सरकार जनभावनाओं से कट चुकी है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि



कांग्रेस का न केवल हमीरपुर जिले में बल्कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जनाधार तेजी से सिमट रहा है। यह परिणाम केवल चुनावी हार नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली के प्रति जनता की नाराजगी का प्रतिबिंब है।

नकड़ोह में श्रद्धा व उत्साह से संपन्न हुआ वार्षिक भंडारा

राजन पुरी

ऊना। कैलाश नगर नकड़ोह स्थित सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर में रविवार को वार्षिक भंडारे का आयोजन बड़ी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ किया गया।

इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र सहित दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर बाबा बालक नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से गणेश पूजन, नवग्रह पूजन तथा बाबा बालक नाथ जी की प्रतिमा के पंचोपचार पूजन के साथ किया गया। इसके उपरांत वैदिक

मंत्रोच्चारण के बीच हवन यज्ञ संपन्न हुआ तथा श्रद्धालुओं द्वारा बाबा जी को पवित्र ध्वजा अर्पित कर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर दौलतपुर संकीर्तन मंडली ने बाबा जी के भजनों एवं भक्तिमय संकीर्तन की मनमोहक प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे और पूरे परिसर में भक्ति की गंगा बहती रही। धार्मिक अनुष्ठानों के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

जाहु वार्ड में दिखा विधायक बनाम पवन कुमार का सीधा मुकाबला, जनता ने दिया स्पष्ट संदेश

पवन धीमान

हमीरपुर। जिला परिषद चुनाव में जाहु वार्ड इस बार सबसे चर्चित सीटों में शामिल रहा, जहाँ मुकाबला केवल प्रत्याशियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसे क्षेत्र में विधायक समर्थित पक्ष और आजाद प्रत्याशी पवन कुमार के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर के रूप में देखा गया।

चुनाव परिणामों में पवन कुमार ने 2341 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। जीत के बाद उन्होंने कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि जनता की जीत है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव



के दौरान सत्ता पक्ष ने पूरा जोर लगाया, लेकिन मतदाताओं ने विकास, जनसंपर्क और किए गए कार्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।

पवन कुमार ने कहा कि चुनाव में धनबल और राजनीतिक प्रभाव का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन

जनता ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाता का वोट होता है। उन्होंने कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव केवल सत्ता के दम पर नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर जीते जाते हैं।

सनोली बीडीसी चुनाव परिणाम पर बवाल, मतगणना में धांधली के लगाए आरोप

राजन पुरी

ऊना। उना ब्लॉक समिति वार्ड नंबर-24 सनोली के चुनाव परिणाम को लेकर विवाद गहरा गया है। भाजपा समर्थित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए हैं। सोमवार को सनोली में ग्रामीणों ने नवनियुक्त प्रधान जर्नेल सिंह की अगुवाई में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि मामले की पारदर्शी जांच नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रधान जर्नेल सिंह के अनुसार ब्लॉक समिति वार्ड-24 की मतगणना उना के राजकीय महाविद्यालय में की गई थी। आरोप है कि प्रारंभिक मतगणना के बाद उना

एसडीएम द्वारा तृतीया देवी को 15 मतों से विजयी घोषित किया गया था। तृतीया देवी को 811 तथा उनकी प्रतिद्वंद्वी चरण को 796 मत प्राप्त हुए थे, जबकि 50 मत नोटा अथवा निरस्त बताए गए थे। आरोप है कि जब तृतीया देवी के कार्डिंग एजेंट विजय प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करते हुए रिकार्डिंग की बात कही। ग्रामीणों का दावा है कि करीब डेढ़ घंटे तक मतगणना प्रक्रिया रुकी रही और बाद में अलग-अलग तथा दूर-दूर स्थित टेबलों पर पुनर्गणना करवाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुनर्गणना के बाद परिणाम पूरी तरह बदल दिए गए। उनके अनुसार अंतिम परिणाम में चरण को 845 तथा तृतीया देवी को 754 मत दर्शाए गए, जबकि नोटा एवं निरस्त मतों की संख्या 58 बताई गई।

बेटे के इंसाफ के लिए मां ने किया आत्मदाह का प्रयास

राजन पुरी

ऊना। हमीरपुर रोड स्थित लोए-लोए कैफे के कर्मचारी दीपांशु के अपहरण और मारपीट मामले में सोमवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब पीड़ित युवक की मां कंचन न्याय न मिलने से अहत होकर आत्मदाह करने के इरादे से पेट्रोल लेकर एमसी पार्क पहुंच गई।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली और किसी भी अप्रिय स्थिति को टाल दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन और कैफे प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अज्ञात लोगों ने



एमसी पार्क से लेकर एमपी कार्यालय तक रोप रैली निकाली और एमपी से मुलाकात करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई की गई होती तो एक मां को आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने के बारे में सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। पीड़ित के साथ आई माता कंचन, लाइव सेणी व संजीव सेणी ने कहा कि यह केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास का सवाल है।

Himachal Pradesh Public Works Department CORRIGENDUM				
The online e-tenders called vide this office letter No. PWH/HD/CBT/1/2024-25-666-675 dated 24.04.2026 (RO No.0685/2026-24/Classified) and due for publication 20.05.2026 at 09.30 AM & further vide corrigendum No.1304-10 dated 19.05.2026 (RO No. 0768/2026-27 classified) due for publication on 02.06.2026 at 9.30 AM is hereby extended as under due to administrative/technical reasons:-				
Key Dates				
S.No.	Description	Old Dates	Amended/new dates	
1	Date of online publication	02.06.2026 (09.30 AM)	08.06.2026 (09.30 AM)	
2	Documents download start and end date/time	02.06.2026 (09.30 AM) up to 08.06.2026 (10.30 AM)	08.06.2026 (09.30 AM) up to 15.06.2026 (10.30 AM)	
3	Bid submission start and end date/time	02.06.2026 (09.30 AM) up to 08.06.2026 (10.30 AM)	08.06.2026 (09.30 AM) up to 15.06.2026 (10.30 AM)	
5	Date of Technical Bid opening	08.06.2026 (11.00 AM)	15.06.2026 (11.00 AM)	

Other terms and conditions of the tenders shall remain unchanged.

Executive Engineer,
HPPWD Division, Haroli, Distt. Una HP.

RO No. 0787/2026-2027

संपादकीय

अमेरिका में भारत व हिंदू विरोधी ताकतें फिर सक्रिय

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के बाद अमेरिका में बैठा भारत व हिन्दू विरोधी गैंग फिर से जाग उठा है क्योंकि बंगाल लहराता भगवा उसे पसंद नहीं आ रहा है। बंगाल में हिंदुत्व की विजय से छद्म धर्मनिरपेक्ष लॉबी को नींद नहीं आ रही है। अमेरिका से जैसे समाचार आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बंगाल चुनावों के दौरान बीजेपी को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उनको अमेरिकी डीप स्टेट का संरक्षण प्राप्त था। विगत दिनों सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सर्वकांत ने सुनवाई के दौरान कॉन्फिडेंस का प्रयोग कर दिया देखते देखते अमेरिका में बैठे कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और कॉन्फिडेंस जनता पार्टी बना दी। इस पार्टी का संस्थापक आम आदमी पार्टी का ही संस्थापक सदस्य अभिजीत दीपके है। कॉन्फिडेंस जनता पार्टी के नाम पर कहा जाने लगा कि अगर युवाओं को बात नहीं सनी गई तो यह कॉन्फिडेंस जनता पार्टी जिसके दो करोड़ से अधिक सोशल मीडिया फॉलोअर वन चुके हैं, देश में क्रांति कर देगी। भारत की विरोधी पार्टियों ने कॉन्फिडेंस जनता पार्टी को हाथों हाथ लिया और टीवी चैनलों पर बहस के दौरान इस पार्टी का भय दिखाते लगे। ये धूल गए कि धरातल पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया के 14 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अमेरिका की एक संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कथित रूप से दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काम करती है। ये संस्था स्वयं को धार्मिक आजादी की स्वयंभू पहरेदार और रक्षक मानती है। वास्तविकता यह है कि यह संस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति अपनी कुटिल मानसिकता के कारण जानी जाती है और अवसर मिलते ही हिंदुओं के प्रति विकृत घृणा का प्रदर्शन करती दिखाई देती है। यह संस्था हिंदुओं के प्रति नफरत से भरी हुई है। इस संस्था ने भारत में धार्मिक आजादी खतरे में हैहू का उद्घोषण किया है। इस बार इसके निशाने पर तीन मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, असम के हिमांता बिसवा सरमा और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद इस सूचि में स्वाभाविक रूप से शुभेंदु अधिकारी का नाम भी जुड़ गया है। इसी अमेरिकी संस्था की एक सुनवाई में अपने आप को तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता व पत्रकार बताने वाला रकीब हमीद नाइक भी पहुंचा और उसने इन लोकप्रिय मुख्यांत्रियों पर जहर उगलते हुए इन पर रोक लगाने की मांग की। रकीब अहमद नाइक मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है और उसका एकमात्र कार्य भारत विरोध है। यह हिंदुत्व वाच के नाम से एक संगठन भी चलाता है जिसका काम हिंदुत्व को घृणा व नफरत के तौर पर टूट कर देना। रकीब का ये संगठन भारत में भी हिंदू राष्ट्रवाद की निगरानी करता है।

नई दिल्ली कार्यालय

एक्शन बालाजी हाउस, वी-244, गजलिंस पार्क, दिल्ली-110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय

शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042

चंडीगढ़ कार्यालय

फर्ट एप्लोर, देश सेक्टर बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय

7/2, थर्ड एप्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय

224, सेक्टर 32पी, करनाल-132001

सोनीपत कार्यालय

ऑफिस no. 11, गांडू एप्लोर पवन मेगा मॉल सुभाष चौक सोनीपत

शिमला कार्यालय

किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला-171001

ऊना कार्यालय

कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय

7/1, बल्लपुर रोड, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

विलक से पहले सोचें : सोशल मीडिया सुरक्षा के मूल मंत्र



सुनील कुमार महला

“ वास्तव में, केवल बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्लेटफॉर्म कंपनियों को अपने एल्गोरिथ्म और फीचर्स सुरक्षित बनाने होंगे। इतना ही नहीं, बच्चों का डेटा संग्रह और उसका व्यावसायिक उपयोग सीमित करने की आवश्यकता है तथा इसमें यह भी कहा गया है कि उनकी निजता की भी रक्षा की जानी चाहिए। इसलिये शब्दों में कहें तो आयोग का यह मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा, निजता और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिले। ”

आज का युग सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट, एआइ का युग है और कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में सोशल मीडिया बच्चों और किशोरों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हालांकि, इसके अनेक लाभ हैं, लेकिन इसके बढ़ते दुष्प्रभावों को लेकर दुनिया भर में चिंता भी बढ़ रही है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई मार्गदर्शिका जारी की है। इस क्रम में बहरहाल, यहां पर पाठकों को बताता चलूँ कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने हाल ही में 'बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सही रखना' (गेटिंग चिल्ड्रेन्स सेफ्टी ऑनलाइन साइट्स) नामक एक मार्गदर्शिका (गाइडलाइंस) जारी की है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों तथा किशोरों के लिए अधिक सुरक्षित बनाना है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह मार्गदर्शिका क्यों जारी की गई है? तो इस प्रश्न का सीधा सा और सटीक उत्तर यह है कि आज बच्चे और किशोर इंटरनेट पर कई प्रकार के खतरों (जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है) का सामना कर रहे हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग, ऑनलाइन यौन शोषण और उल्पीड़न, गोपनीयता (प्राइवैसी) का उल्लंघन, हिंसक, अश्लील या आत्महत्या को बढ़ावा देने वाली सामग्री, सोशल मीडिया की लत बढ़ाने वाले फीचर (इनफाइनाइट स्काल, आटो-प्ले, लगातार नोटिफिकेशन आदि) भ्रामक जानकारी और हेत स्पीच आदि। हाल फिलहाल, यदि हम यहां पर पर इस मार्गदर्शिका की प्रमुख बातों की बात करें तो इसमें 'सेफ बाइ डिजाइन' सिद्धांत को अपनाते की बात कही गई है। अर्थात् ऐसे प्लेटफॉर्म की डिजाइन ही ऐसी हो कि बच्चों की सुरक्षा पहले से सुनिश्चित हो।

वास्तव में, केवल बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्लेटफॉर्म कंपनियों को अपने एल्गोरिथ्म और फीचर्स सुरक्षित बनाने होंगे। इतना ही



नहीं, बच्चों का डेटा संग्रह और उसका व्यावसायिक उपयोग सीमित करने की आवश्यकता है तथा इसमें यह भी कहा गया है कि उनकी निजता की भी रक्षा की जानी चाहिए। इसलिये शब्दों में कहें तो आयोग का यह मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा, निजता और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिले। हानिकारक सामग्री, ऑनलाइन शोषण और साइबर बुलिंग को रोकने के लिए मजबूत निगरानी और शिक्षात्मक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। यह भी कहा गया है कि सरकारों को ऐसे कानून और नियम बनाने चाहिए जो बच्चों के डिजिटल अधिकारों और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि बच्चों को इंटरनेट से दूर करना ही समस्या का समाधान नहीं है। उन्हें शिक्षा, संवाद और जानकारी के लिए डिजिटल दुनिया तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित, जिम्मेदार और अधिकार-आधारित डिजिटल वातावरण तैयार करें। कहना गलत नहीं होगा कि वास्तव में यह मार्गदर्शिका सरकारों, टेक कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए एक दिशा-निर्देश है,

ताकि किशोरों को ऑनलाइन दुनिया के खतरों से बचाते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। यहां पर यह गौरतलब है कि विश्व में कई देशों ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या उसे नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। पाठक जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने इस संबंध में कानून भी बना दिया है, जबकि फ्रांस, स्पेन, यूनान, डेनमार्क, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी ऐसे उपायों पर काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने से बच्चे अधिक जोखिम वाले और अनियंत्रित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं, जिससे खतरे और बढ़ सकते हैं। हाल फिलहाल, यहां पाठकों को बताता चलूँ कि पिछले कुछ सालों में भारत में भी इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सच तो यह है कि देश में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट की उपलब्धता ने बच्चों को कम उम्र में ही डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया है। हाल के एनुअल स्टेट्स आफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर)-2024 सर्वेक्षण के अनुसार 14-16 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 82% बच्चे स्मार्टफोन चलाना

जानते हैं, जबकि 76% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। लगभग 90% बच्चों के घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है। भारत में 2024 की शुरुआत तक 75 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता और 46 करोड़ से अधिक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता थे, जिससे बच्चों की ऑनलाइन भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। बढ़ती डिजिटल पहुंच ने बच्चों को शिक्षा, जानकारी और संवाद के नए अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, गोपनीयता के खतरे, फर्जी जानकारी और डिजिटल लत जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसी कारण बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक और नीतिगत विषय बन गया है। पाठक जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल गतिविधियों के विस्तार से बच्चों की इंटरनेट पर निभरता काफी बढ़ गई है। कई रिपोर्टों के अनुसार लंबे समय तक सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों की एकाग्रता, सोचने-समझने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, भ्रामक जानकारी और अनुचित सामग्री तक पहुंच जैसी समस्याएं भी गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसी स्थिति में केवल प्रतिबंध लगाना पर्याप्त समाधान नहीं माना जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। अभिभावकों की निगरानी, डिजिटल साक्षरता, सोशल मीडिया उपयोग की समय-सीमा, ऑटोप्ले और अनंत स्क्रॉलिंग जैसी सुविधाओं पर नियंत्रण तथा बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। भारत की परंपरा संतुलन और समग्र दृष्टिकोण की रही है, इसलिए यहां भी ऐसा समाधान खोजने की जरूरत है जो बच्चों को इंटरनेट के लाभों से वंचित किए बिना उन्हें सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रख सके।



विचार

कब तक चलेगा अगली पेशी अगले साल का सिलसिला

मनोज कुमार अग्रवाल

अगली पेशी अगले साल यह देश की अदालतों में होता रहा है लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय में देरी को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए सभी हाईकोर्ट्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए सभी फैसले अधिकतम तीन महीने (90 दिन) के भीतर सुनाने अनिवार्य हैं। वहीं, जमानत से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है पूर्व में भी पूर्व सीजेआई सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र और सत्तारूढ़ नेता समय समय पर देश की न्याय व्यवस्था में देरी की समस्या का समाधान खोजने का वायदा और बयान करते रहे हैं लेकिन घर बार ढाक के वहीं तीन पात। न्याय में देरी का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन जब अदालतें बहस पूरी होने के बाद भी वर्षों तक फैसले सुरक्षित रखती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं रह जाती, बल्कि न्याय के मूल सिद्धांत पर सवाल खड़ा करती है। यह वह कड़वी सच्चाई है कि अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं और न्याय की उम्मीद लिए लोग तारीख पर तारीख काटते रहते हैं। कई मामलों में फैसला तब आता है, जब पीटेंट की उम्र, आर्थिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा लगभग खत्म चुकी होती है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि देर से मिला न्याय क्या सचमुच न्याय कहलाया जा सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार निचली अदालतों को सचेत कर चुका है। एक बार फिर से हाईकोर्टों में फैसलों में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर चिंता जताते

हुए स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद उसे तीन महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए। यदि तीन महीने तक फैसला नहीं आता है, तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को वह मामला चीफ जस्टिस के सामने रखना होगा। तहत, सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए सभी फैसले अधिकतम तीन महीने (90 दिन) के भीतर सुनाने अनिवार्य हैं। वहीं, जमानत से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है पूर्व में भी पूर्व सीजेआई सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र और सत्तारूढ़ नेता समय समय पर देश की न्याय व्यवस्था में देरी की समस्या का समाधान खोजने का वायदा और बयान करते रहे हैं लेकिन घर बार ढाक के वहीं तीन पात। न्याय में देरी का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन जब अदालतें बहस पूरी होने के बाद भी वर्षों तक फैसले सुरक्षित रखती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं रह जाती, बल्कि न्याय के मूल सिद्धांत पर सवाल खड़ा करती है। यह वह कड़वी सच्चाई है कि अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं और न्याय की उम्मीद लिए लोग तारीख पर तारीख काटते रहते हैं। कई मामलों में फैसला तब आता है, जब पीटेंट की उम्र, आर्थिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा लगभग खत्म चुकी होती है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि देर से मिला न्याय क्या सचमुच न्याय कहलाया जा सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार निचली अदालतों को सचेत कर चुका है। एक बार फिर से हाईकोर्टों में फैसलों में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर चिंता जताते

हुए स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद उसे तीन महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए। यदि तीन महीने तक फैसला नहीं आता है, तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को वह मामला चीफ जस्टिस के सामने रखना होगा। तहत, सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए सभी फैसले अधिकतम तीन महीने (90 दिन) के भीतर सुनाने अनिवार्य हैं। वहीं, जमानत से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है पूर्व में भी पूर्व सीजेआई सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र और सत्तारूढ़ नेता समय समय पर देश की न्याय व्यवस्था में देरी की समस्या का समाधान खोजने का वायदा और बयान करते रहे हैं लेकिन घर बार ढाक के वहीं तीन पात। न्याय में देरी का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन जब अदालतें बहस पूरी होने के बाद भी वर्षों तक फैसले सुरक्षित रखती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं रह जाती, बल्कि न्याय के मूल सिद्धांत पर सवाल खड़ा करती है। यह वह कड़वी सच्चाई है कि अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं और न्याय की उम्मीद लिए लोग तारीख पर तारीख काटते रहते हैं। कई मामलों में फैसला तब आता है, जब पीटेंट की उम्र, आर्थिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा लगभग खत्म चुकी होती है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि देर से मिला न्याय क्या सचमुच न्याय कहलाया जा सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार निचली अदालतों को सचेत कर चुका है। एक बार फिर से हाईकोर्टों में फैसलों में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर चिंता जताते

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मंडैदपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संवाहित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के वरदानों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आररनआई: HPHIN / 2012 / 48072

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन इंडिया कार्यालय, कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना हिमाचल प्रदेश-174303 से प्रकाशित एवं अर्थ प्रकाश प्रेस, अर्थ प्रकाश भवन, सेक्टर-29डी, चंडीगढ़ से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी

समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)

स्थानीय संपादक : पंकज शर्मा (9418026789)

ई-मेल : actionindia@shimla@gmail.com

actionindia@gmail.com

एक्शन इंडिया शिमला कार्यालय: किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

एक्शन इंडिया ऊना कार्यालय: कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना, हिमाचल प्रदेश-174303

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उदाहरण को बार में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रकाशक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या सत्यता नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।



आलेख

क्षणिक स्वार्थ से नागरिक बोध तक

मनमोहन प्रकाश, शिक्षाविद्

मनुष्य को पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी माना जाता है। उसके पास सही और गलत, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के अंतर करने की अद्भुत क्षमता है। हमारा अनुभव, शिक्षा, सामाजिक मूल्य और कानून इस विवेक को और निखारते हैं। इसके बावजूद, एक कड़वा और विचित्र सच यह है कि हममें से अधिकांश लोग अनेक गंभीर गलतियाँ जानबूझकर करते हैं। हम भली-भांति जानते हैं कि हमारा आचरण अनुचित है और इसके परिणाम आत्मघाती हो सकते हैं, फिर भी हम उन्हें बार-बार दोहराते हैं। आज के मशीनी और उपभोक्तावादी युग में यह केवल भारतीय समाज

की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण वैश्विक मानव समाज की एक सहज प्रवृत्ति बन चुकी है। हाँ, भारत जैसे विशाल, घनी आबादी और सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में यह समस्या अधिक मुखर और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, हम सब जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। तेज हॉर्न, अनियंत्रित डीजे और लाउडस्पीकर का शोर बच्चों, वृद्धों, रोगियों और बेजुबान जानवरों को असहनीय पीड़ा देता है, साथ ही विद्यार्थियों की एकाग्रता को भंग करता है। इसके बावजूद, विवाह, धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में हम ध्वनि की गरिमा और कानूनी

मर्यादा को ताक पर रख देते हैं। यही स्थिति पर्यावरण को लेकर भी है। सड़कों पर कूड़ा फेंकना, नदियों, तालाबों और पूजनीय जलाशयों में प्लास्टिक, रासायनिक अपशिष्ट और यहाँ तक कि पूजा-सामग्री बहा देना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। हम जानते हैं कि भूजल, कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, फिर भी हम उनका बेरहमी से दोहन करते हैं। मोबाइल वॉर्मिंग (वैश्विक तापन) और जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोज महसूस करने के बाद भी 'विकास' के मुखौटे के पीछे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है, तारीख काटे हैं। इसका प्रति कोई सामूहिक पश्चाताप नहीं दिखता।

क्या पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन पायेगा?

सौरभ वाघोंय

आज की पत्रकारिता: संघर्ष, जिम्मेदारी और विश्वास की परीक्षा बन कर रह गई है। लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तंभों में पत्रकारिता को केवल कहने को वही विशेष स्थान प्राप्त है। पत्रकारिता केवल समाचारों का संकलन और प्रसारण भर नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने, सत्ता से प्रश्न पूछने और जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देने का सशक्त माध्यम भी है। किंतु वर्तमान समय में पत्रकारिता अनेक चुनौतियों, दबावों और संघर्षों के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में पत्रकारिता की भूमिका, जिम्मेदारी और विश्वसनीयता पर गंभीर चिंतन आवश्यक हो गया है। अभी ३० मई पत्रकारिता दिवस बीता है लेकिन सत्ता की तरफ से सिरफ रसम अदायगी? क्या वाकई पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संविधान के तहत बन पायेगा या हम प्रचार विरादरी सिर्फ गाढ़े गवाड़े ढोल पीटते रह जायेंगे? पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ कहने भर का चौथा स्तंभ रह जायेगा। यह एक ज्वलंत विषय है। आज सूचना क्रांति का युग है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने समाचारों के प्रसार

को अत्यंत तेज बन दिया है। जहाँ पहले एक समाचार को पाठकों तक पहुंचने में घंटों या दिनों का समय लगता था, वहीं अब कुछ ही सेकंड में खबरें दुनिया भर में पहुंच जाती हैं। लेकिन इस तेजी के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है—सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की चुनौती। फर्जी खबरें, आधी-अधूरी जानकारियाँ और भ्रामक प्रचार पत्रकारिता की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य निष्पक्षता, सत्यता और जनहित की रक्षा करना है। लेकिन आज कई बार व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, टीआरपी को दौड़ और राजनीतिक प्रभाव के कारण पत्रकारिता अपने मूल मूल्यों से भटकती दिखाई देती है। समाचारों की प्रसुति में सनसनीखेजता बढ़ रही है, जबकि तथ्यों की गहराई और निष्पक्ष विश्लेषण का अपेक्षित महत्त्व नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है। सूरी और जर्मनी स्तर पर कार्य करने वाले पत्रकारों का संघर्ष भी कम नहीं है। अनेक पत्रकार सीमित संसाधनों में काम करते हुए जनसमस्याओं को उजागर करने का प्रयास करते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनि्युक्त 276 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

टीम एक्शन इंडिया
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने कैम्प कार्यालय स्थित मुख्यसेवाक सदन में विभिन्न विभागों के लिए चयनित कुल 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर नवनि्युक्त अभ्यर्थियों से कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जनसेवा के नए दायित्व की शुरुआत है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने वन विभाग के अंतर्गत 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 65 एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चयनित 14 अभ्यर्थी शामिल हैं। इस

अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जनसेवा के नए दायित्व की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि वर्षों के परिश्रम, अनुशासन, संघर्ष और धैर्य के बाद युवाओं को यह सफलता प्राप्त हुई है, जो उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और समर्पण का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने नकल माफियाओं और भ्रष्टाचार पर प्रभावी



अंकुश लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में युवाओं की सफलता का आधार केवल उनकी योग्यता और मेरिट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि

पिछले साढ़े चार वर्षों में लगभग 33 हजार युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। उन्होंने नवचयनित कार्मिकों से अपेक्षा की कि वे अपनी कार्यकुशलता,

जिम्मेदारी
वर्षों के परिश्रम, धैर्य के बाद युवाओं को यह सफलता प्राप्त हुई है, जो उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और समर्पण का प्रमाण है : धामी

विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्मिक प्रदेश के सुनियोजित विकास में योगदान देंगे, प्राविधिक शिक्षा विभाग से जुड़े युवा तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देंगे, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कार्मिक मातृ एवं बाल कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करेंगे तथा वन विभाग में चयनित युवा राज्य की वन संपदा एवं जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत-2047 के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार भी विकसित

उत्तराखंड के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जहां घोषणा से अधिक डिलीवरी, वादों से अधिक परिणाम और राजनीति से अधिक विकास को महत्व दिया जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवचयनित युवा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हुए उत्तराखंड के विकास और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

आमजन की समस्याओं का समयबद्ध हो निस्तारण: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

टीम एक्शन इंडिया
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की। उनके प्रार्थना पत्र लिए और उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री ने सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण समयसमया के भीतर हो। विलंब होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कुछ बच्चों से शिक्षा के बारे में भी पूछा और अभिभावकों से कहा कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, क्योंकि पढ़ा-लिखा बच्चा ही सशक्त भारत की नींव है। मुख्यमंत्री योगी के समक्ष राजस्व व पुलिस से जुड़े भी कुछ मामले आए। मुख्यमंत्री ने उनका संज्ञान लिया



और कहा कि लंबित राजस्व वादों का समयसमया के भीतर निस्तारण किया जाए। छह महीने से अधिक लंबित वादों के कारणों की समीक्षा की जाए। उचित कारण न होने पर भी यदि निस्तारण में विलंब होता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान हो।

अधिकारी पूरी संवेदनशीलता से सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सभी को न्याय और हर पात्र को योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो। जस्तकतमंद के चेहरे पर खुशहाली लाना शासन-प्रशासन का दायित्व है।
बेटा। तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो
हापुड़ से एक बच्ची अपने

जनता दर्शन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया

बेटी पढ़कर आगे बढ़ेगी तो देश व समाज आगे बढ़ेगा: मुख्यमंत्री योगी

अभिभावक के साथ आई थी। उसने अपने परिवार की माली स्थिति का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि किस क्लास में हो, इस पर बच्ची ने कक्षा-7 बताया और आगे की पढ़ाई में आने वाली बाधाओं का भी जिक्र किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि घर जाओ और सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो। अभिभावक से कहा कि शिक्षित बच्चा ही सशक्त भारत की नींव है। अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे, आप बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोजित समारोह में मेधावी छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरिट में छात्राओं ने छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किया है। यह सुखद संकेत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी पढ़कर आगे बढ़ेगी और देश व समाज आगे बढ़ेगा। मेधावियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी सोशल मीडिया में न्यूनतम समय लगायें। सोशल मीडिया के ज्यादातर तथ्य झूठे होते हैं। समाचार पत्र अवश्य पढ़ें। देश व समाज के बारे में जानकारी रखिए। अपनी परम्परा, संस्कृति व विरासत व अपने परिवेश के बारे में जानकारी रखें।

गुरुग्राम में मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के 312 नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी

ईआरवी
ये सभी वाहन आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन यानी ईआरवी के रूप में काम करेंगे



टीम एक्शन इंडिया
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा पुलिस के बेड़े में शामिल 310 नई मोटरसाइकिलों और दो कारों को सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी वाहन आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन यानी ईआरवी के रूप में काम करेंगे। वाहन कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत होंडा मोटर फाउंडेशन द्वारा हरियाणा पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के रिस्पांस टाइम को सराहना करते हुए कहा कि देश में ईआरवी का औसत

रिस्पांस टाइम लगभग 18 मिनट है, जबकि हरियाणा पुलिस ने इसे घटाकर सात मिनट तीन सेकेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इसे सुशासन का वास्तविक स्वरूप बताया। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस विभाग में आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था कर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत किया है। ये ईआरवी उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने जनता से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी अपील की। नए वाहनों में से गुरुग्राम को 60

मोटरसाइकिलें और एक होंडा एलिक्ट्रिक मीली है। फरीदाबाद को 40 मोटरसाइकिलें और एक होंडा एलिक्ट्रिक दी गई है। बाकी 210 मोटरसाइकिलें हरियाणा के अन्य जिलों को भेजी गई हैं। डीजीपी अजय सिंहल ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन अत्याधुनिक वाहनों के शामिल होने से राज्य में कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने बताया कि ईआरवी संकरी गलियों में भी कम समय में मौके पर पहुंचेंगे, जिससे जनता की सुरक्षा और पुख्ता होगी।

स्वस्थ समाज-परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी: राज्यपाल



टीम एक्शन इंडिया
भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि स्वस्थ समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएँ अपने व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए समय निकालें। संतुलित आहार, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। राज्यपाल पटेल सोमवार को भोपाल स्थित लोक भवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर शुभारंभ अवसर पर संदीपनि सभागार में उपस्थित महिलाओं से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को स्वच्छता किट प्रदान की। संदीपनि सभागार और सिविल डिस्पेंसरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का अवलोकन किया। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल पटेल के

जीवनशैली
महिलाएँ अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें: राज्यपाल

जन्म दिवस के अवसर पर लोक भवन में सोमवार को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था। अस्थिरोग संबंधी चिकित्सकीय जाँच के लिए बोन मिनरल डेनसिटी जाँच और परामर्श शिविर का आयोजन डिस्पेंसरी में तथा एच.पी.सी. और महिला स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जागरूकता के लिए चिकित्सकीय परामर्श सत्र संदीपनि सभागार में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, उप सचिव सुनील दुबे सहित लोकभवन के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल पटेल की सवैधानिक मूल्यों और अंत्योदय के प्रति निष्ठा, प्रेरणादायी: डॉ. यादव

टीम एक्शन इंडिया
भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के जन्मदिवस पर सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित लोकभवन पहुंचकर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्रम और बाबा महाकाल की प्रतिकृति भेंट कर उनका अभिवादन किया। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि राज्यपाल मंगुभाई पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संवैधानिक मूल्यों



और अंत्योदय के प्रति आपकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता तथा प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है। मां नर्मदा से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रदान करें।
मंगुभाई पटेल : सक्षिप्त जीवन परिचय

मंगुभाई पटेल का जन्म 1 जून 1944 को गुजरात के नवसारी जिले में हुआ। समाज सेवा को अपना प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाने के साथ उनकी अभिरुचि खेल, संगीत तथा अध्ययन में रही है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की

सम्मान
डॉ. यादव ने अंग वस्त्रम और बाबा महाकाल की प्रतिकृति भेंट कर उनका अभिवादन किया

शुरुआत स्थानीय निकायों से की और वर्ष 1982 से 1987 तक नवसारी नगर पालिका के सदस्य रहे। वे भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों पर रहे, जिनमें गुजरात भाजपा आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष तथा भाजपा गुजरात के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष एवं

महासचिव प्रमुख हैं। वे वर्ष 1990 से 2017 तक लगातार गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे। गुजरात सरकार में उन्होंने जनजातीय कल्याण, वन एवं पर्यावरण, तथा कुटीर एवं उद्योग विभागों में मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों निभाईं। साथ ही वे गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे। जनजातीय कल्याण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। उन्होंने सिक्कल सेल उन्मूलन अभियान, जनजातीय विकास, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आजीविका योजनाओं, पेसा

अधिनियम के क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी अनेक नवाचारों को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से जनजातीय अध्ययन एवं विकास केंद्रों तथा नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिला। मंगुभाई पटेल ने जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, युगांडा, कैमरून, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अनेक देशों की यात्राएं कर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे कई पुस्तकों और प्रकाशनों के लेखक भी हैं, जिनमें मौन का उद्बोध, मन की बात, अखंडता का उल्लेख तथा संकल्प का सामर्थ्य प्रमुख हैं।

डबल इंजन नहीं, डबल इंतजार शास्त्र चल रहा है- अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार पर विकास परियोजनाओं में देरी को लेकर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में गहलोत ने डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए इसे डबल इंतजारशास्त्र करार दिया। गहलोत ने कहा कि परियोजनाओं में देरी केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला मुद्दा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है।



किया गया है ताकि यह समझाया जा सके कि परियोजनाओं में देरी केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला मुद्दा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है।

नीति आयोग की बैठक से पहले शुभेंदु ने सभी विभागों से मांगी रिपोर्ट

रिपोर्ट तलब
मुख्यमंत्री ने विभागों के सचिवों को पांच जून तक अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया



टीम एक्शन इंडिया
कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आगामी 11 जून को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक से पहले राज्य सरकार के सभी विभागों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री ने

सभी विभागों के सचिवों को पांच जून तक अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। नवानु सत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की समग्र स्थिति, विकास योजनाओं और वित्तीय आवश्यकताओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर

रहे हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने राज्य के सभी विभागों की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों, चुनौतियों और आवश्यकताओं का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। सत्रों का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार का मानना है कि पिछले 15 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार की कथित असहयोगपूर्ण नीति के

कारण राज्य को केंद्र से मिलने वाले कई वित्तीय लाभ और अधिकार पूरी तरह नहीं मिल सके। अब सरकार का ध्यान केंद्र से राज्य के बकाया और वैध हिस्से को प्राप्त करने पर है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री सक्रिय रूप से पहल कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, नीति आयोग की बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, केंद्रीय सहायता, अनुदान और वित्तीय आवंटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि जून के अंत में राज्य सरकार अपना पूर्ण बजट पेश कर सकती है।

गाँव के द्वार पहुँची डिजिटल सरकार : बड़ेकनेरा का सेवा सेतु मॉडल बना ग्रामीण सुशासन की नई मिसाल

टीम एक्शन इंडिया
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कांडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का निरीक्षण कर ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल सेवा सेतु की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद कर योजनाओं की पहुंच, पारदर्शिता और प्रभाव के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाओं और सेवाओं का



लाभ ग्रामीणों को उनके गांव में ही सहज, सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु अभियान और अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं, जिनसे आमजन को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर

लगाने से मुक्ति मिल रही है। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान ग्राम की हितग्राही श्रीमती कौशल्या मानिकपुरी ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से महतारी वंदन योजना की राशि प्राप्त हो रही है, जिससे घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि

सुलभ
ग्रामीणों तक त्वरित, सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से खेती-किसानी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिली है। इसी प्रकार श्रीमती सुमति मानिकपुरी, श्रीमती अमिल मानिकपुरी तथा श्रीमती पंचमती बघेल ने मुख्यमंत्री को बताया कि महतारी वंदन योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाया है और परिवार

की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता दी है। वृद्धावस्था पेंशन और महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त कर रही श्रीमती वैकटरमणा जंगम ने भी योजनाओं की नियमित उपलब्धता पर संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उनसे चर्चा करते हुए कहा कि सरकार प्रत्येक गरीब, किसान और महिला तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में संचालित सेवा सेतु अभियान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं को ग्रामीणों तक त्वरित, सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है।

झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मिलीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी

टीम एक्शन इंडिया
रांची। झारखंड मंत्रालय में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिष्टाचार मुलाकात की। यह भेंट मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में हुई। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने सोहार्दपूर्ण वातावरण में एक-दूसरे का अभिवादन किया। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुलाकात के दौरान राज्य



के विकास, महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं तथा जनहित के विभिन्न मुद्दों पर भी सामान्य चर्चा हुई। हालांकि, इस

संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है और न ही किसी विशेष विषय पर विस्तृत बयान जारी किया गया है।

राज्यपाल ने स्व-गणना अभियान का शुभारम्भ किया

जनगणना

» जनगणना-2027 के अंतर्गत स्व-गणना का प्रथम चरण 1 जून से 15 जून तक किया जाएगा संचालित

पंकज शर्मा

शिमला। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज लोक भवन से जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्व-गणना अभियान का शुभारम्भ किया। यह अभियान 1 जून से 15 जून, 2026 तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्व-गणना प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेशवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय



दायित्व में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। इस अवसर पर निदेशक, जनगणना संचालन, हिमाचल प्रदेश, दीप शिखा शर्मा और विभाग के चरित्र अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने राज्यपाल को डिजिटल जनगणना प्रक्रिया तथा इसके विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। राज्यपाल ने प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त जनगणना के महत्व

पर बल देते हुए कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश और प्रदेश की भावी विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों तथा प्रशासनिक निर्णयों की आधारशिला है। कविन्द्र गुप्ता ने प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे 1 जून से 15 जून के बीच स्व-गणना प्रक्रिया को प्राथमिकता के

जनगणना आंकड़े राष्ट्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे सिद्ध

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होती हैं। नागरिकों द्वारा सही जानकारी प्रदान करने से योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचाने तथा समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के बाद विकास की बदलती आवश्यकताओं और नई चुनौतियों को देखते हुए जनगणना-2027 से प्राप्त होने वाले आंकड़े राज्य एवं राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं दुर्गम राज्यों में समग्रतः और प्रभावी आंकड़ों संकलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्व-गणना अभियान को विशेष प्राथमिकता प्रदान की गई है।

आधार पर पूर्ण कर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

राज्यपाल ने नागरिकों को स्व-गणना पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त होने वाली स्व-गणना पहचान संख्या को सुरक्षित रखने का परामर्श दिया। अभियान के अगले चरण में 16 जून से 15 जुलाई, 2026 तक घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित की जाएगी।

स्व-गणना कर चुके लोगों द्वारा अपनी पहचान संख्या उपलब्ध करवाने से जनगणना कार्य अधिक सुगमता एवं दक्षता के साथ सम्पन्न हो सकेगा। कविन्द्र गुप्ता ने सटीक एवं प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि प्रभावी प्रशासन और योजनाबद्ध विकास के लिए सही आंकड़ों का होना अत्यंत आवश्यक है।

वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए टोंगलेन ट्रस्ट को हर संभव सहयोग देगी प्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री



टीएम एक्शन इंडिया

शिमला। टोंगलेन ट्रस्ट धर्मशाला के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज ट्रस्ट के निदेशक धेरचिन ग्याल्तसेन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री टाकुर सुखविन्द सिंह सुखू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय के लिए भूमि पट्टे की मांग से अवगत करवाया। यह विद्यालय वंचित एवं बेसहारा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर

रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये तथा 14 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को 2,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने वंचित एवं

जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा और मानवीय सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की पहल समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस अवसर पर राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक हरीश जनारथा, ट्रस्टी दोरजे तथा पार्षद पलकित नेगी भी उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव-2026 के अंतर्गत कैनवास ऑफ दि हिल्स कला महोत्सव का आयोजन

टीएम एक्शन इंडिया

शिमला। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव-2026 के अंतर्गत कला एवं संस्कृति को समर्पित विशेष आयोजन कैनवास ऑफ दि हिल्स का आयोजन ऐतिहासिक रिज मैदान, शिमला में किया गया। इस अनूठे कला महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिष्ठित चित्रकारों एवं कलाकारों ने भाग लेकर शिमला की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपने कैनवास पर सजीव रूप में उकेरा।

इस अवसर पर उपायुक्त एवं अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव समिति के अध्यक्ष अनुपम कश्यप ने सभी प्रतिभागी कलाकारों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही कलाकारों ने अपनी रचनात्मक कृतियों उपायुक्त को भेंट स्वरूप प्रदान कीं। इन उत्कृष्ट चित्रों



की भविष्य में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिससे कला प्रेमियों को हिमाचल की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्राप्त होगा।

उपायुक्त ने कहा कि इस विशेष पहल के तहत कलाकारों ने रिज मैदान एवं उसके आसपास के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक परिवेश का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हुए लाइव पेंटिंग और स्केचिंग की। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के

अगले चरण में कलाकार हिमालयी क्षेत्र की अद्भुत प्राकृतिक छटा को चित्रित करने के लिए स्पीट घाटी का भ्रमण भी करेंगे।

उन्होंने कहा कि कैनवास ऑफ दि हिल्स कला महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देशभर के कलाकारों को एक साझा मंच प्रदान करना, कला के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना तथा शिमला की अनुपम सुंदरता को रचनात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है।

जुबल-नावर-कोटखाई में पंचायत चुनाव में मिली प्रचंड जीत

टीएम एक्शन इंडिया

शिमला। जुबल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली प्रचंड जीत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर द्वारा गत साढ़े तीन वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर जनता की स्पष्ट मोहर है। यह बात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुबल-नावर-कोटखाई के अध्यक्ष जितेंद्र मैहता ने प्रेस को जारी एक बयान में कही।

उन्होंने कहा कि जुबल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की सभी जिला परिषद वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसी प्रकार पंचायत समिति जुबल की सभी 15 सीटों पर जनता ने कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाया इसके विपरीत भाजपा का सूपड़ा साफ हुआ। पंचायत समिति कोटखाई में कांग्रेस ने 11 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।

चंबा जिला परिषद पर कांग्रेस का कब्जा

हामिद खान

चंबा। पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से जिला परिषद पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है जिला परिषद के 18 वार्डों में से घोषित परिणामों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 10 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। यह तो अब पक्का है कि जिला परिषद का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से ही होगा।

चंबा जिला परिषद में कुल 18 वार्ड हैं इनमें से 10 वार्ड कांग्रेस के कब्जे में आ गए हैं। कांग्रेस ने जिन वार्डों में सफलता हासिल की है उनमें सनवाल वार्ड से निर्मला भूटानी, चारु वार्ड से रजनी मल्होत्रा, चकल वार्ड से अंजू कुमारी, सरोल वार्ड से लियाकत अली, करवाल से अंशुल कुमार, बयाना से रेखा ठाकुर, किहार से कमला योगी, नैनी खड्ड से प्रदीप शर्मा, मोतला से कुसुम लता, तथा खर्णा से सुभाष चंद्र विजय हुए हैं।



अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इसके समर्थित पांच उम्मीदवार भी विजय हासिल कर पाए हैं जिनमें भरमौर वार्ड से पूर्व विधानसभा स्पीकर स्वर्गीय तुलसीराम की पत्नी लीला शर्मा, करवास से सुनीता कुमारी, करियां वार्ड से राज सिंह तथा कथेड़ से दिव्या ज्योति शामिल हैं।

इस बीच तीन आजाद उम्मीदवार भी सफल हुए हैं जिन में ज्युंता से मीनाक्षी कपूर, बकपुर से इंदिरा कपूर तथा गैरवा से सुनील शर्मा। अब सब की नजर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदों पर टिकी है।

डीएवी पब्लिक स्कूल चम्बा में श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक मनाया गया डीएवी स्थापना दिवस



हामिद खान

चंबा। डीओ एओ वीओ पब्लिक स्कूल चम्बा में आज डीओ एओ वीओ स्थापना दिवस बड़े हर्ष, उल्लास एवं वैदिक परम्पराओं के साथ मनाया गया। इस पवन अवसर पर विद्यालय परिसर पूरी तरह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और देशभक्ति के रांग में ढूँढा नजर आया। कार्यक्रम का शुभारम्भ वैदिक मंत्रोच्चारण एवं भव्य हवन-यज्ञ से हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार गुलेरिया, समस्त अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विद्यालय के शास्त्री पंकज

कुमार ने अपनी सुमधुर आवाज और वैदिक मंत्रोच्चारण से सम्पूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक एवं भक्तिमय बना दिया। विद्यालय के संगीत अध्यापक श्री आशीष जी द्वारा प्रस्तुत वैदिक भजनों ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को भाव-विभोर कर दिया। इस मौके पर छात्रों द्वारा भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ जिसमें छात्रों ने डीओ एओ वीओ संस्था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी एवं महात्मा इंंदिराजी के जीवन, संघर्षों और आदर्शों पर प्रभावशाली व्याख्यान दिए।

अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव-2026 में हिंदी, पहाड़ी और गजल गोष्ठियों के आयोजन के लिए हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच ने जताया जिलाधीर अनुपम कश्यप का आभार

टीएम एक्शन इंडिया

शिमला। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष एवं प्रख्यात लेखक एस आर हरनोट ने अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव-2026 में हिंदी और पहाड़ी कवि गोष्ठियों के साथ गजल गोष्ठी के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए जिलाधीर अनुपम कश्यप और अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव समिति का हिमाचल के लेखकों की तरफ से आभार जताया है। ये आयोजन श्यामला कवि सम्मेलन और श्यामला मुशायरा के नाम से हो रहे हैं जिसमें स्थानीय लेखकों के साथ हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से 100 से अधिक लेखक भाग लेंगे।

एस आर हरनोट ने अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव समिति के सौजन्य से जानकारी दी कि 8 जून को हिंदी कवि सम्मेलन का सत्र: सत्र में 30 और अपराह्न सत्र में 35 कवि भाग लेंगे। जबकि 9 जून, 2026 को आयोजित पूरे दिन चलने वाली



पहाड़ी कवि गोष्ठी में तीस से अधिक पहाड़ी कवि भाग लेंगे। 10 जून दोपहर बाद गजल गोष्ठी (श्यामला मुशायरा) होगा जिसमें हिमाचल के विभिन्न स्थानों से लगभग बीस उर्दू गजलकार शिरकत करेंगे। शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के इतिहास में यह पहली बार है जब इतने रचनाकारों को एक साथ मंच और सम्मान दिया जा रहा है। निरिहदेह पहल और परिकल्पना साहित्य अनुसूची और कुशल प्रशासनिक जिलाधीर अनुपम कश्यप जी की रही है जिसने लिए एस आर हरनोट ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है।

हरनोट ने सभी आमंत्रित लेखकों से निवेदन किया है कि वे इस पहल का स्वागत करें। हालांकि यह स्वाभाविक है कि किसी आयोजन में किसी प्रदेश के समस्त रचनाकारों को एक साथ आमंत्रित करना मुश्किल होता है फिर भी सौ से अधिक लेखकों को बुलाना किसी बड़े साहित्य उत्सव से कम नहीं है। जिला प्रशासन के सौजन्य से शीघ्र ही कहानी संवाद का भी आयोजन किया जाएगा और बच्चों के लिए भी। उन्होंने हिमाचल के हर जिला प्रशासन से प्रत्येक नेतृत्व, लीडरों और उत्सवों में साहित्य संवाद और इस तरह की गोष्ठियां आयोजित करने की अपील की है ताकि हर लेखक की भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। हरनोट ने जिला प्रशासन को आश्वासन दिया है कि उनका हिमालय मंच इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेगा।

टोल टैक्स वृद्धि को लेकर हिमाचल बॉर्डर मैहतपुर पर चक्का जाम



राजन पुरी

जुना। हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार उग्र रूप धारण करता जा रहा है। सोमवार को एक बार फिर पंजाब की विभिन्न जलथेबंदियों ने हिमाचल के प्रवेश द्वार मैहतपुर में एकत्रित होकर टोल टैक्स के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लोगों की भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए टोल टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने की मांग दोहराई। इस दौरान हिमाचल से

पंजाब जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जबकि पंजाब से हिमाचल आने वाले वाहनों को आवाजाही की अनुमति दी गई। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सड़क जाम की बल्कि धरने के दौरान टोल बैरियर पर हो रही टैक्स वसूली भी बंद करवा दी। प्रदर्शनकारियों में जन कल्याण कमेटी के प्रधान कश्मीर सिंह नंगली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया यह टैक्स आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है और इसे किसी भी सूत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खुफिया तंत्र फेल, राजनीतिक पंडित चित ! हमीरपुर में आशीष शर्मा के सियासी तूफान ने उड़ाए सारे समीकरण

पवन धीमान

हमीरपुर। जिला परिषद चुनावों में इस बार हमीरपुर की राजनीति ने ऐसा करवट ली कि खुफिया एजेंसियों से लेकर बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषकों तक के सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए। चुनावी मैदान में कौन आगे है, कौन पीछे है और किसकी नैया डूबने वाली है, इसका दावा करने वाले तमाम सूत्रधार परिणाम आने के बाद पूरी तरह गलत साबित हुए। अब राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है कि आखिर सदर विधायक आशीष शर्मा ने ऐसा कौन-सा सियासी चक्रव्यूह रचा कि विरोधी देखते ही रह गए और भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीत का परचम लहरा गए।

चमनैड वार्ड से लेकर जंगल रोपा और अन्य सीटों तक चुनावी माहौल आखिरी दिन तक बेहद दिलचस्प बना रहा। फोल्ड रिपोर्ट्स में कभी किसी प्रत्याशी को आगे



बताया जा रहा था तो कभी किसी को। सोशल मीडिया पर भी अलग-अलग दावे किए जा रहे थे। लेकिन मतगणना के दिन जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। चमनैड वार्ड की कहानी तो किसी राजनीतिक फिलिम से कम नहीं रही। यहां भाजपा समर्थित प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ, विरोधियों ने इसे अपनी जीत मान लिया और जश्न की तैयारियां शुरू कर दीं। लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद प्रत्याशी दोबारा मैदान में उतरे और चुनावी हवा का रुख ही बदल गया। चुनाव प्रचार के दौरान हर दिन नए समीकरण बनते और बिगड़ते रहे, लेकिन अंत में हैप्पी पहलवान ने बाजी मारकर

विरोधियों के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। दूसरे वार्ड में टिकट वितरण को लेकर मचे बवाल को विपक्ष अपनी ताकत समझ रहा था। माना जा रहा था कि नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। लेकिन सुरेश कुमार सोनी को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता एकजुट हुए और जिस सीट को विरोधी आसमान जीत मान रहे थे, वह भी भाजपा समर्थित खेमे



की झोली में चली गई। सबसे बड़ा उलटफेर जंगल रोपा वार्ड में देखने को मिला। समय तुकना चर्चाओं में आखिरी समय तक नरेश कुमार दर्जी और अनिल कुमार शर्मा के नाम सबसे ऊपर चल रहे थे। राजनीतिक पैनाल, चौपाल और चाय की दुकानें इसी चर्चा से गर्म थीं कि मुकामबला इन्हीं दोनों के बीच है। विधायक समर्थित प्रत्याशी अनिल कुमार सोनी को कई लोग

तीसरे नंबर का टिकट देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मतगणना पूरी हुई, सारे अनुमान धुएँ में उड़ गए। जिस प्रत्याशी को लोग दौड़ से बाहर मान रहे थे, वही जीत का ताज पहनकर सामने आया। राजनीतिक जानकारों का

कहना है कि यह केवल चुनावी जीत नहीं बल्कि राजनीति की जीत है। विधायक आशीष शर्मा ने जिन सीटों पर दौंव लगाया, वहां आखिरी समय तक पूरी ताकत झोंक दी। गांव-गांव बैठकों, जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज ने ऐसा माहौल बनाया कि विरोधियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। परिणाम आने के बाद कांग्रेस खेमे में मायूसी और भाजपा

समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कई स्थानों पर लोगों का कहना था कि इस बार चुनाव ने यह साबित कर दिया कि फोल्ड रिपोर्ट, सर्वे और राजनीतिक चर्चाएं अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है।

जीत के बाद विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास, विश्वास और काम करने वालों का साथ दिया है।

वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिला परिषद चुनावों में मिली जीत आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक तस्वीर का संकेत भी मानी जा रही है। हमीरपुर में फिलहाल एक ही सवाल गूँज रहा है—क्या यह सिर्फ जीत है या फिर सदर विधायक आशीष शर्मा के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव की नई पटकथा?

संक्षिप्त खबरें

जिप में प्रचंड जीत होने पर जुग्गा के राजमहल में भव्य जश्न आयोजित



चमन शर्मा

शिमला। जिला परिषद के चम्पियाण वार्ड नंबर 9 में प्रचंड जीत मिलने पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी खुश विक्रम सेन के सम्मान में जुग्गा के राजमहल के प्रांगण में एक भव्य जश्न का आयोजन किया गया जिसमें क्योथल क्षेत्र के हजारों लोगों ने खुश विक्रम सेन को बधाई दी। राजमहल के प्रांगण में ढोल नगादों की पारंपरिक धुनों पर महिलाओं और पुरुषों ने जीत की खुशी में खूब नाटी डाली। गौर रहे कि जिला परिषद के चम्पियाण वार्ड से खुश विक्रम सेन को कुल 13752 मत मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भूपेन्द्र सिंह को 3771 मत मिले। अर्थात् खुश विक्रम सेन को कुल 9981 मतों अंतर से भारी जीत हासिल की।

कार्यक्रम में सांसद राज्य सभा हर्ष महाजन, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, जिला शिमला भाजपा अध्यक्ष केश चौहान, जिला भाजपा प्रवक्ता जितेंद्र भोत्रका सहित काफी संख्या में आए भाजपा प्रत्याशियों ने खुश विक्रम सेन को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी।

जुग्गा के प्रधान रामलाल, पंकज सेन, रामकृष्ण वर्मा, प्रीतम ठाकुर, राघव शर्मा, पवन

शर्मा, दुर्गा सिंह ठाकुर सहित अनेक लोगों ने कहा कि यह कसुपेटी निर्वाचन क्षेत्र का भविष्य खुश विक्रम सेन में देखते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि यदि आगामी विधान सभा चुनाव में खुश विक्रम सेन को भाजपा हाईकमान टिकट देती है तो निश्चित रूप से कसुपेटी में 25 वर्षों के अंतराल उपरान्त कमल अवश्य खिलेगा।

खुश विक्रम सेन से जब इस बारे पूछा गया कि जब आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इस पर उन्होंने बताया कि यदि भाजपा हाईकमान का आदेश होगा तो उसकी अक्षर:क्ष अनुपालना की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल बतौर जिला परिषद सदस्य वह चम्पियाण वार्ड की 17 पंचायतों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखकर रखी जाएगी और समाधान के लिए भरपूर प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि बने 25 वर्षों से कसुपेटी निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होने का बावजूद भी यह विधानसभा क्षेत्र विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों इत्यादि में बहुत पिछड़ा हुआ है।